बजट में यूपी की पहल को मिला राष्ट्रीय विस्तार

एक जिला एक उत्पाद योजना देशभर में लागू, हस्तिनापुर के बहाने सांस्कृतिक एजेंडे पर नजर

अखिलेश वाजपेयी

लखनऊ। केंद्र सरकार ने आम बजट के जरिये उत्तर प्रदेश सरकार की शुरुआत को राष्ट्रीय विस्तार दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जिलों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी विशिष्ट पहचान को परवान चढ़ाने के लिए शुरू की गई एक जिला-एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) को बजट में शामिल किया गया है। वहीं, महाभारत कालीन हस्तिनापुर को पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करने का संकल्प व्यक्त कर उत्तर प्रदेश के पौराणिक सरोकारों के साथ अपने जुड़ाव व सांस्कृतिक एजेंडे पर भी नजर टिकाए रखी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यूपी खास महत्व रखता है। उन्होंने यूपी से चुनाव लड़कर यह बता दिया था। अब बजट भाषण में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहकर कि प्रधानमंत्री मोदी का 'एक जिला-एक निर्यात' का सपना साकार हो, इसलिए वह उन राज्यों को सहायता देंगी जो 'एक उत्पाद-एक जिला' पर फोकस करेंगे। इस तरह उन्होंने यूपी में शुरू की गई 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना को राष्ट्रीय विस्तार दिलाकर दूसरे राज्यों को यूपी से प्रेरणा लेने का संदेश दिया है।

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जिस जिले में जाते थे, वहां की विशिष्टता का उल्लेख करते हुए बताते थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने हर जिले के लोगों को एक खास हुनर दिया है। यह हुनर लंबे समय तक उनके जिले की पहचान और अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा। पर, केंद्र और राज्य सरकारों के ध्यान न देने से यह दम तोड़ गया। मोदी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग, बनारस के साड़ी उद्योग, भदोही के कालीन उद्योग आदि का जिक्र किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की इस आकांक्षा को ओडीओपी योजना बनाकर परवान चढ़ाया। अब केंद्र ने योगी सरकार की ओडीओपी योजना को न सिर्फ सही दिशा में चलने का प्रमाणपत्र दे दिया है बल्कि इसे पंख भी लगाने की कोशिश की है।

इस तरह भी काम

अर्थशास्त्री प्रो. एपी तिवारी कहते हैं कि भले ही बजट में सीधे-सीधे उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ी उल्लेखनीय घोषणा न दिख रही हो लेकिन प्रदेश का महत्व बरकरार रखा गया है। न सिर्फ 'ओडीओपी योजना को विस्तार देकर ही उत्तर प्रदेश को महत्व दिया गया है, बल्कि हस्तिनापुर को पुरातत्व स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करके भी यूपी और मुख्यमंत्री योगी के संकल्पों को महत्व देने का संदेश दिया है। अभी पिछले महीने ही मुख्यमंत्री योगी ने मेरठ के पास महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगरी की बदहाली का संज्ञान लिया था। विधान परिषद सदस्य और पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के पत्र के बाद उन्होंने पर्यटन विभाग और संस्कृति निदेशालय को हस्तिनापुर का गौरव बहाल करने के लिए कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया था।

निशाना यह भी

आजादी के बाद हस्तिनापुर की बदहाली का तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 6 फरवरी 1949 को हस्तिनापुर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। तबसे कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन हस्तिनापुर अपने पुनरुद्धार की प्रतीक्षा करता ही रहा। अब केंद्र सरकार ने बजट में इसे शामिल करके सांस्कृतिक सरोकारों के सम्मान का ध्यान रखने का संदेश देने के साथ ही कांग्रेस पर अपने ही पूर्ववर्ती नेताओं के काम को पूरा न कराने को लेकर निशाना साधने का भी जरिया तलाश लिया है। राम और रामायण के साथ महाभारत के जरिये भी सांस्कृतिक सरोकारों को परवान चढ़ाने की तैयारी की है।

Amar Ujala page 10 2/2/20